



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2020/00232(111/2020)

दर्ज तिथि:-25.09.2020

1. मानी पत्नी उदा पुत्री केता
 2. गेरो पत्नी मोडा पुत्री सोना
- जाति रबारी निवासी गांधव खुर्द तहसील गुडामालानी-बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरा पुत्र पैलाद
2. खंगारा पुत्र पैलाद
3. हमीरा पुत्र पैलाद
4. रूपो पत्नी पैलाद
5. जाति रबारी निवासी गांधव खुर्द तहसील गुडामालानी-बाड़मेर
6. तहसीलदार गुडामालानी

.....असल विप्रार्थीगण

.....तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:- श्री रामजीवन विश्नोई

अप्रार्थीगण:- श्री डालूराम चौधरी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251ए

राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-09.09.2024

प्रार्थना-पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 261/155 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम गांधव खुर्द तहसील गुडामालानी में पहुँच



के प्रयोजन के लिए मौके पर खसरा संख्या 488/155 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम गांधव खुर्द तहसील गुड़ामालानी से होते हुए नहर के साथ चालू रास्ता तक पहुंच हेतु एकमात्र विकल्प है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में विप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488/155 वाके ग्राम गांधव खुर्द में से प्रार्थीगण के आवागमन हेतु रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः खसरा संख्या 488/155 वाके ग्राम गांधव खुर्द में से नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। अंत में प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं होने तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 30 फुट चौड़ाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विधिवत तामील होने के उपरांत विप्रार्थी संख्या 3 के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 व 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान सरकार सिंचाई विभाग की मौके पर चालू नहर तक पहुंचने के लिये रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी का उक्त रास्ते के माध्यम से नहर से अवैधानिक रूप से पानी को अपने खेत तक पहुंचाने के अप्रत्यक्ष उद्देश्य से रास्ता चाहा गया है। साथ ही अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488/155 के सेढे करीब 15 से 18 फिट की ऊँचाई में नहर का निर्माण किया गया है। उक्त नहर के दोनों तरफ मौके पर रास्ता चालू है। अगर प्रार्थी को उक्त मौके पर चालू रास्ते तक अप्रार्थीगण की आराजी से होकर रास्ता दिया भी जाता है तो प्रार्थीगण व्यावहारिक रूप से उक्त रास्ते का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 488/155 तथा 493/155 वाके ग्राम गांधव मौके पर संयुक्त रूप से मिले हुए खेत हैं। अगर प्रार्थी को आराजी खसरा संख्या 488/155 वाके ग्राम गांधव से होकर रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी की आराजी व्यावहारिक रूप से मौके पर विभक्त हो जाएगी। जिससे अप्रार्थीगणों को नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 261/155 तक जाने के लिये सबसे लघुत्तम रास्ता निकटतम हाईवे के खसरा संख्या 523/101 से अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 493/155 से होकर विकल्प उपस्थित है। परंतु प्रार्थीगण गलत मंशा से नहर के पानी तक पहुंच रखने हेतु उक्त रास्ते का आवेदन गलत मंशा से प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने तथा नहर के पानी तक पहुंच रखने हेतु रास्ता मांगने के आधार पर उक्त आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

मौका रिपोर्ट

3. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम-1955 के नियम-68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 13.06.2022 द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई। उक्त मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र को दिनांक 05.06.2023 को बहस सुनते हुए खारिज किया गया।

जिरह-प्रार्थी

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने-ए-जिरह प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी की प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 261/155 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम गांधव खुर्द तहसील गुड़ामालानी में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर खसरा संख्या 488/155 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम गांधव खुर्द तहसील गुड़ामालानी से होते हुए नहर के साथ चालू रास्ता तक पहुँच हेतु एकमात्र विकल्प है जिसके अतिरिक्त प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 30 फुट चौड़ाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जिरह-अप्रार्थी

5. अभिभाषक विप्रार्थीगण ने दौराने-ए-जिरह अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निम्न प्रकार निवेदन किया:-
1. प्रार्थी द्वारा राजस्थान सरकार सिंचाई विभाग की मौके पर चालू नहर तक पहुँचने के लिये रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा किसी कट्टाण मार्ग के जुड़ाव रखने वाले रास्ते हेतु आवेदन नहीं किया है। केवल प्रार्थी का उक्त रास्ते के माध्यम से नहर से अवैधानिक रूप से पानी को अपने खेत तक पहुँचाने के अप्रत्यक्ष उद्देश्य से रास्ता चाहा गया है।
 2. अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 488/155 तथा 493/155 वाके ग्राम गांधव मौके पर संयुक्त रूप से मिले हुए खेत हैं। अगर प्रार्थी को आराजी खसरा संख्या 488/155 वाके ग्राम गांधव से होकर रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी की आराजी व्यावहारिक रूप से मौके पर विभक्त हो जाएगी। जिससे अप्रार्थीगणों को नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर प्रार्थीगण को नहर तक पहुँचने हेतु रास्ता दिया जाए तो प्रार्थी की संयुक्त आराजी के मध्य से रास्ता नहीं दिया जाकर किसी एक किनारे से रास्ता दिया जावे।
 3. प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 261/155 तक जाने के लिये सबसे लघुत्तम रास्ता निकटतम हाईवे के खसरा संख्या 523/101 से अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 493/155 से होकर विकल्प उपस्थित है। अगर प्रार्थी को इस रूट/मार्ग से रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही लघुत्तम रास्ता निकटतम हाईवे के खसरा संख्या 523/101 से अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 493/155 से होकर दिये जाने वाले रास्ते में आई भूमि की एवज में अप्रार्थी को भूमि से क्षतिपूर्ति की जावे।
6. उभय पक्षकारों ने प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 261/155 तक जाने के लिये सबसे लघुत्तम रास्ता निकटतम हाईवे के खसरा संख्या 523/101 से अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 493/155 से होकर विकल्प पर सहमति व्यक्त की। इस पर लघुत्तम रास्ता निकटतम हाईवे के खसरा संख्या 523/101 से अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 493/155 से होकर दिये जाने वाले रास्ते में आई भूमि की एवज में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 261/155 में से अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 488/155 के सेढे भूमि के बदले भूमि देने पर सहमति व्यक्त की। उक्त प्रस्ताव पर अप्रार्थीगण ने सहमति व्यक्त की।

कानूनी-प्रावधान

7. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका-रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है जो कि इस प्रकार है-

251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where -

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम-1955 के नियम-68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो कि इस प्रकार है-

68. Application under Sec. 251-A. - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.

69. Enquiry and disposal of application. - On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

विश्लेषण

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम-1955 के नियम-68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251-क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत आमद-रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तों के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है-

1. प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम-1955 के नियम-68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम प्रथम शर्त प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैं:-
 1. प्रथम स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर चालू है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते से ही आवागमन करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।
 2. द्वितीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर अतिक्रमण की वजह से चालू नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते को मौके पर अतिक्रमण हटवाकर चालू करवाने के लिये संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।
 3. तृतीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को प्रथम शर्त को पुष्ट मानते हुए द्वितीय शर्त पर परखा जाना चाहिए।
8. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या-2 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में उक्त शर्त के तथ्य का खण्डन करते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 261/155 तक जाने के लिये सबसे लघुत्तम रास्ता निकटतम हाईवे के खसरा संख्या 523/101 से अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 493/155 से होकर विकल्प उपस्थित है। तहसीलदार गुड़ामालानी दिनांक 13.06.2022 को प्रेषित मौका रिपोर्ट में उक्त संदर्भ में कोई कथन नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में राजस्व ग्राम गांधव के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार प्रकरण उक्त तृतीय स्थिति के अंतर्गत आता है एवं शर्त संख्या 01 की पूर्णरूप से पुष्टि प्रतीत होती है।

निष्कर्ष

9. अतः प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य सहमति होने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्रावली तथा तहसीलदार गुड़ामालानी दिनांक 13.06.2022 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन एवं उभयपक्षकारान की सहमति के आधार पर विश्लेषित निष्कर्षानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही आदेश दिये जाते हैं कि निकटतम हाईवे के खसरा संख्या 523/101 से अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 493/155 से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 261/155 तक प्रार्थी द्वारा वांछित/इच्छित चौड़ाई, जो कि चौड़ाई में अधिकतम 30 फीट तक हो, के रास्ते में निहित होने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 261/155 के अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 488/155 के सेढे प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 261/155 में से समान रकबा की आराजी के रकबे को कलमजन किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 09.09.2024 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर